PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

कम उत्पादन और अनुपलब्धता जैविक खेती में मुख्य बाधा– 'कट्स' सर्वे

जयपुर, 28 अक्टूबर, 2015।
जयपुर स्थित प्रमुख उपभोक्ता संस्था 'कट्स' द्वारा 'स्विडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन' (एस.एस.एन. सी), स्वीडन के आर्थिक सहयोग से जैविक उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोओर्गेनिक' नाम से एक परियोजना राज्य के छः जिलों में पिछले दो वर्षों से चलाई जा रही है। परियोजना के अंतिम चरण में किये गये सर्वे के परिणाम के अनुसार 97.6 प्रतिशत किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जानते है, लेकिन कम उत्पादन व जैविक खाद व बीज की अनुपलब्धता के कारण 69.6 प्रतिशत किसान जैविक व रासायनिक खेती कर रहे हैं, जबकि 16.3 प्रतिशत किसान केवल जैविक खेती कर रहे हैं।

उक्त तथ्य परियोजना के तहत आज आयोजित राज्य स्तरीय पैरवी एवं शोध प्रस्तुतिकरण बैठक में प्रस्तुत किये गयें। यह सर्वेक्षण छह जिलों की 51 ब्लॉक की 102 ग्राम पंचायतों में किया गया। कुल 3122 हितधारक सर्वेक्षण में भागीदार थें, जिसमें 1605 किसान और 1517 उपभोक्ता शामिल हैं, इनमें 40 प्रतिशत महिलाएं भी शामिल हैं।

विपणन की तकनीकी जानकारी के अभाव में किसान अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। सर्वे के दौरान किसानों ने यह सुझाव भी दिया कि जागरूकता का प्रसार करके व सरकारी एजेंसियों पर जैविक उत्पादों की खरीद का दबाव बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा मिल सकता है।

डॉ. शीतल प्रसाद शर्मा, निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान ने जैविक खेती के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम मिट्टी की शक्ति को बढ़ाना होगा। डॉ. ए.के. गुप्ता, प्रोफेसर, एस.के.एन. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ने कहा कि जैविक खेती से किसानों व उपभोक्ता, दोनों को ही फायदा है।

डॉ. एस. मुखर्जी, प्रोफेसर, कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा ने जैविक खेती के उत्पादों के लिए घरेलू उपयोग व निर्यात हेतु विशेष जैविक उत्पाद केन्द्रों की स्थापना करनी होगी। वर्धमान बाफना, महाप्रबन्धक, मोरारका फाउण्डेशन ने ग्राम पंचायत स्तर पर जैविक उत्पादों की बिक्री हेतु दुकानें खोलनी चाहिए।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' ने कहा कि जैविक खेती बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और किसानों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को जैविक उत्पादों हेतु उपभोक्ता केन्द्रित नीति बनानी होगी न कि निर्यात को ध्यान में रखकर।

दीपक सक्सेना, वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक ने परियोजना की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण दिया वहीं, राम कुमार झा, नीति विश्लेषक ने अतिम शोध परिणामों का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में कृषि व खाद्य विभाग, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा जोबनेर कृषि विश्वविधालय के अधिकारी, जैविक खेति पर काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं सहित 80 से अधिक भागीदारों ने भाग लिया।

———————————————————————————————————————

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
दीपक सक्सेना (97999 96095)
'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
डी– 218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर– 302 016, भारत
दूरभाषः 91–.5133259, 2282821 / 2282482, फैक्सः 91–141–4015395
ईमेलः ds@cuts.org; वेबसाइटः http:/www.cuts-international.org